साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 11-17 अक्टूबर 2021, वर्ष-7, अंक-28

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज में जन्म के साथ ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

किसानों को वाट्सएप पर मिलेगी खसरे की कॉपी

विशेष संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में सशक्त तरीके से ई-गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है। जनकल्याण एवं सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भूमि से जुड़े दस्तावेज खसरा-खतौनी, अक्स सहित अन्य दस्तावेजों की कापी 10 रुपए (प्रति कॉपी) की दर से वाट्सएप पर देने की घोषणा की। यही नहीं, अब बच्चे के जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में चरित्र प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की भी घोषणा की। अब स्व-घोषणा के आधार पर नियुक्ति भी दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी।

मप्र में सशक्त तरीके से हो रही ई-गवर्नेंस की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में राजस्व अभिलेखों का शुद्धीकरण परखाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान हितग्राहीमूलक योजनाओं के सरलीकरण और एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन के लिए अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पहले योजनाओं के क्रियान्वयन पर हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके आधार पर प्रशिक्षण में चर्चा होगी और योजनाओं की प्रक्रिया की बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग की जाएगी। 15 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक प्रदेश में अभियान चलाकर यह देखा जाएगा कि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सुराज के लिए सुनिश्चित प्रयास करने का फैसला लिया है।

प्रमुख घोषणाएं

- समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए आवेदन से हितलाभ वितरण तक की प्रक्रिया आनलाइन होगी।
- आय, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन सेवाओं के लिए इंटरनेट मीडिया पर आवेदन लें।
- ग्राम पंचायत स्तर तक लोकसेवा केंद्रों का विस्तार होगा। पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र खोले जाएंगे।
- प्रदेश में ई-रुपी की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू करेंगे। इसी से आयुष्मान भारत और छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मप्र में ढाई लाख फर्जी और 80 हजार मृत किसानों को मिली पीएम सम्मान निधि

अपात्र को सम्मान अन्नदाता से छल

» फिर धोखाः अफसरों ने सूची जांच कर नहीं बनाई, इसलिए अपात्रों को मिली राशि

» अच्छी बातः गड़बड़ी पकड़ी तो सीएम सम्मान निधि अपात्रों के खातों में जाने से बच गई

» अब तकः तीन साल में 4 से 7 किश्त ले चुके हैं। अपात्र, हर किश्त में दो हजार डाले गए

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

सरकार की योजनाओं में फर्जीवाड़ा होना आम बात है। अक्सर यही होता है कि, जो पात्र हितग्राही होते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता औ जो अपात्र होते हैं, वो फायदा उठा ले जाते हैं। दरअसल, इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़ी गड़बडी उजागर हुई है। मप्र में दो लाख 51 हजार 391 ऐसे किसान है, जिनके खातों में योजना के 19 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपार ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। पैसा खाते में आते ही लोगों ने इन्हें तत्काल निकाल भी लिया।

यहां बड़ी बात यह है कि इन लाभार्थी किसानों में कई आयकर दाता हैं तो कहीं एक ही परिवार के कई लोगों के खातों में पैसे डाल दिए गए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 80 हजार से ज्यादा ऐसे किसान मिले हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। भोपाल में ऐसे किसान 2,570 पाए गए हैं। फिलहाल इन सभी से जिला प्रशासन ने वसूली शुरू कर दी है।

मुरैना में भी मिले अपात्र

इधर, प्रदेश के मुरैना जिले में 7,107 अपात्र किसान छांटे गए हैं, जिनसे 5 करोड़ 87 लाख की सम्मान निधि की वसूली होनी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4000 रुपए दिया जाता है। वहीं श्योपुर जिले में 10 हजार किसान हैं।

पंजाब में सबसे ज्यादा 5 लाख 62 हजार किसान अपात्र

2018 में लागू हुई थी योजना

2.51 लाख अपात्र किसान

19.57 करोड़ खाते में डाले

2570 भोपाल में अपात्र

5.87 करोड़ मुरैना में वसूली

सरकार ने भी स्वीकारा| हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी कि देशभर में 42 लाख 16 हजार 643 किसान जो पात्र नहीं थे, उनके खाते में 29 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी गई है।

भोपाल में 2570 अपात्र| भोपाल जिले में 63 हजार 430 पात्र किसानों को 73 करोड़ 98 लाख 64 हजार रुपए का भुगतान 2018 से अब तक किया जा चुका है। भोपाल में कुल रजिस्टर्ड किसानों की संख्या एक लाख 26 हजार है। इसमें से सिर्फ 2570 किसानों से सम्मान निधि की गाइड-लाइन के दायरे में नहीं आने के कारण राशि वसूली जाएगी।

पूरे प्रदेश में दो लाख के करीब अपात्र किसान हैं। इनमें से डेढ़ लाख किसान ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, उसके बाद किसान सम्मान निधि उनके खाते में गई। इसमें किसानों को दोष नहीं दे सकते। लेकिन 50 हजार के करीब ऐसे भी हैं, जो नौकरी पेशा, आयकर चुकाने वाले हैं, फिर भी योजना के हितग्राही बन गए। इन सभी से वसूली के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए गए हैं।

ज्ञानेश्वर बी पाटील, आयुक्त, भू-अभिलेख

मप्र में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। जबकि दूसरी ओर उन्हें वसूली के नोटिस थमाए जा रहे हैं। शाजापुर जिले की सात तहसीलों में 7550 किसानों को 5 करोड़ 60 लाख की रिकवरी के नोटिस मिले हैं। इसी तरह अन्य जिलों में भी किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो पहले अफसरों गाज गिरे।

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा मप

किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी 'साथी' परियोजना

प्रमुख संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश 'साथी (सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एंड होलिस्टिक इंटीग्रेशन) परियोजना' लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। यह परियोजना के किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर भारत व आत्मनिर्भर मप्र के स्वप्न को साकार करने में भी सहायक होगी। यह बात प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कही। योजना के अंतर्गत 100 साथी बाजार, 7319 वेअर हाउस, 2133 कोल्ड स्टोरेज, 405 ग्रेडिंग यूनिट और 2126 कृषि उत्पाद प्र-संस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन पर लगभग 3 हजार 380 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। नाफेड के मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के 26 जिलों गुना, सतना, अशोकनगर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर, कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया सहित दमोह के 100 विकासखंडों के लिए बनाई गई है।

योजना के होंगे 5 घटक

» साथी परियोजना के 5 घटक साथी कृषक समूह, साथी प्र-संस्करण केन्द्र, साथी उद्योग, साथी बाजार तथा कॉमन फेसिलिटी सेंटर होंगे।

» गांवों में एक समान उत्पादन करने वाले किसानों के समूह बनाए जाएंगे। उत्पादों के मूल्य संवर्धन का कार्य पंचायत स्तर पर साथी प्र-संस्करण केन्द्र करेंगे।

हमने निर्देश दिए हैं कि योजना को व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए, जिससे इसका लाभ किसानों को मिले। योजना की नोडल एजेंसी नाफेड को भी कहा गया है कि विस्तृत कार्य-योजना बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाई जाए। साथ ही वहां से इसके लिए फंडिंग भी प्राप्त की जाए। योजना प्रारंभ में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखंडों में लागू होगी।

महेंद्र सिंह सिसौदिया, पंचायत मंत्री

जबलपुर में सरोगेसी से 15 गाय गर्भवती

मध्यप्रदेश में गौ माता बन रहीं सरोगेट मदर

-लक्ष्य-किसानों और डेयरी संचालकों को अच्छी नस्ल की गाय देना

संवाददाता, जबलपुर

जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कमाल के काम कर रहा है। अब उसने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गजब का तरीका खोज निकाला है। यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गायों में सरोगेसी शुरू कर दी है। सड़क पर घूमने वाली आवारा गायों पर ये प्रयोग किया गया और वो गर्भवती हो गयीं। सरोगेसी से ना केवल गायों का संरक्षण और संवर्धन होगा, बल्कि नई और अच्छी नस्ल की गाय तैयार हो जाएंगी।

सड़कों पर घूमने वाली गाय और गौशालाओं में छोड़ी गई गाय भी अच्छी नस्ल के गाय या बछड़ों को जन्म दे सकती हैं। उम्मीद की ये किरण जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। यहां के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से बेसहारा गायों को न केवल नया जीवनदान दिया है, बल्कि इन गायों को सबसे अच्छी नस्ल की गाय को जन्म देने के लिए तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि के जरिए 15 गायों को गर्भवती किया है।

कैसे होता है भ्रूण प्रत्यारोपण

भ्रूण प्रत्यारोपण विधि में बैल के अच्छे सीमन को वैज्ञानिक अच्छी नस्ल और ज्यादा दूध देने वाली गाय के अंदर डालते हैं। ऐसी गाय को डोनर कहा जाता है। जब गाय के अंदर भ्रूण परिपक्व हो जाता है तब सक्शन विधि के जरिए भ्रूण को गाय से निकाला जाता है और फिर सेरोगेट गाय में डाला जाता है।

30 गाय पर प्रयोग, 15 पर सफल

विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन की मदद से करीब 30 गाय ली थीं। उनमें ये प्रयोग किया गया। सभी गायों की देखरेख वैज्ञानिक खुद कर रहे हैं और जो गाय गर्भवती हुई हैं उनके पोषण आहार का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्यारोपण विधि के जरिए विश्व विद्यालय की गौशाला में 15 गायों को गर्भवती किया जा चुका है। ये इसी महीने अक्टूबर के अंत तक अच्छी नस्ल के बछड़े या बछिया को जन्म देंगी। यह प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ है।

गाय का भी भला

बेहद कम लागत में विवि ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। इस काम के लिए विवि में ही लैब तैयार की गई है। प्रोजेक्ट का मकसद किसानों और डेयरी संचालकों को अच्छी नस्ल की गाय देना है। साथ ही उन गायों का संरक्षण करना है जिन्हें सड़कों या गौशालाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। विवि में इससे पहले हाल ही में कुत्ते के खून से आंख की झिल्ली बनायी गयी थी।

डॉ. सीता प्रसाद तिवारी, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि

रीवा में 36 से घटकर 32 हजार हेक्टेयर पहुंचा रकबा

विंध्य में घट गया प्याज का रकबा

बीते सीजन में बारिश की वजह से विंध्य क्षेत्र के साथ-साथ रीवा जिले के प्याज किसानों को निराशा मिली है। नतीजन वर्ष 2022 के लिए रीवा जिले में 36 हजार हेक्टेयर से रकबा घटकर 32 हजार हेक्टेयर पहुंच गया है।

बारिश से खराब हो गई थी 15 लाख क्विंटल प्याज

संवाददाता, रीवा

उद्यानिकी विभाग की मानें तो वर्ष 2021 में 32 हजार हेक्टेयर में प्याज की फसल ली गई थी, जिसमें 7 हजार हेक्टेयर की प्याज मई-जून माह में हुई बारिश की वजह से खराब हो गई। ऐसे में किसानों की करीब 15 लाख क्विंटल प्याज का नुकसान हुआ है। जिससे आने वाले सीजन के लिए प्याज लगाने वाले किसानों की संख्या कम हो गई है।

मऊगंज-नईगढ़ी में सर्वाधिक उत्पादन

नईगढ़ी और गंगेव ब्लॉक में रीवा जिले का 40 प्रतिशत प्याज का उत्पादन होता है। वहीं इसके बाद त्योंथर ब्लॉक के किसान प्याज की फसल को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा हनुमना, मऊगंज, सिरमौर, हुजूर, गुढ़ सहित मनगवां ब्लॉक में भी प्याज का उत्पादन किया जा रहा है।

प्याज के रकबे में कमी

पिछले कई वर्षों से बारिश में बनी अनिश्चितता की वजह से प्याज के रकबे में कमी आती जा रही है। बीते वर्ष 36 हजार हेक्टेयर रकबा था, जो इस वर्ष घटकर 32 हजार हेक्टेयर हो गया है। प्याज खुदाई के लिए मई और जून माह उपयुक्त होता है। वहीं मई-जून के अंतिम दिनों में बारिश हो जाती है। जिसकी वजह से किसानों की प्याज खराब होती है। यही वजह है कि किसान अब धीरे-धीरे प्याज का रकबा कम कर रहे हैं।

किसानों को नहीं मिलता भाव

किसानों के पिछले दो-तीन वर्षों से प्याज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। रीवा जिले में किसानों की प्याज 2000 रुपए क्विंटल बिकती है। वहीं पड़ोसी जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ढाई हजार रुपए क्विंटल भाव से बिकती है। जबकि प्याज की खेती में लाभ कमाने के लिए किसानों को एक क्विंटल प्याज की कम से कम तीन हजार से लेकर साढ़े तीन हजार रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलना चाहिए।

रीवा जिले में किसान सिर्फ रबी सीजन में प्याज की फसल लेते हैं। जिसकी बोवनी जनवरी माह में होती है। फसल तैयार होने के बाद प्याज की खुदाई मई और जून महीने में की जाती है। ऐसे में इस बार मई और जून महीने में चक्रवाती तूफान की वजह से बारिश हो गई। जिससे अधिकांश किसान बारिश के पूर्व प्याज की खुदाई कर ली थी, लेकिन 7 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में लगी प्याज की खुदाई नहीं कर सके। ऐसे में 32 हजार हेक्टेयर की जगह 25 हजार हेक्टेयर की फसल ही किसानों को मिली है।

योगेश कुमार पाठक, सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग, रीवा

70 लोग जुड़े, एक परिवार को रोजगार भी मिला

गाय प्रेम में बना लिया नियमित गौ-ग्रास परिवार

परिवार को मिल गया रोजगार

नियमित रूप से हरी घास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा रहे टिंकू कुशवाह बताते हैं कि वह कोली से जमीन लेकर घास उगाते हैं और गोग्रास परिवार को उपलब्ध कराते हैं। नियमित रूप से घास बिकने से उन्हें रोजगार भी मिल गया है। जिससे उनके परिवार का पोषण होने लगा है। उनके परिवार के सभी सदस्य इसमें सहयोग करते हैं।

संवाददाता, विदिशा

गोसेवा के लिए एक युवक के मन में ऐसा प्रेम उमड़ा कि उसने नियमित गो ग्रास परिवार ही बना लिया। आठ लोगों से शुरू हुए परिवार में अब तक 70 लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें शहर के अलावा पुणे, नागपुर, इंदौर, भोपाल और आयरलैंड तक से युवक शामिल हैं। गायों को 12 माह हरी घास मिल सके। इसके लिए एक परिवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे उस परिवार को रोजगार भी मिला है। परिवार प्रमुख राम शर्मा बताते हैं कि तीन साल पहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वह गौ-शाला पहुंचे थे, जहां 12 माह हरी घास नहीं मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से चर्चा की और बाजार से घास खरीदकर गौ-शाल जाने लगे। फुटकर में घास महंगी मिल रही थी। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति से चर्चा की जो 12 माह हरी घास उपलब्ध कराने तैयार हो गया। इसके बाद वह नियमित घास लेकर गौ-शाला जाने लगे। लोगों को जानकारी मिलती गई और कारवां बढ़ता गया। संख्या अधिक हो जाने के कारण अब एक माह में दो से तीन लोगों का ही नंबर आता है जो 500-500 रुपए का सहयोग करते हैं। जिससे एक से डेढ़ हजार रुपए तक का नियमित रूप से घास गौवंश को उपलब्ध होने लगा है।

मैसेज कर दिलाते हैं याद

गौ-ग्रास परिवार का मोबाइल पर ग्रुप बनाया गया है, जिसमें परिवार से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। ग्रुप पर एक दिन पहले मैसेज कर दिया जाता है कि कल किन सदस्यों का नंबर रहेगा। इसके बाद संबंधित सदस्य उस दिन तय समय पर गौ-शाला पहुंच जाते हैं। जहां वह घास लेकर पहुंचे व्यक्ति को राशि उपलब्ध कराकर घास खरीदते हैं और अपने हाथों से गायों को खिलाते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से जुड़े हैं वह उसे ऑनलाइन राशि उपलब्ध कराते हैं।

-शिवराज सरकार अब बनाएगी विकास की योजना

प्रदेश के 57 हजार गांवों की बनेगी कृषि कुंडली

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 56 हजार से ज्यादा गांवों की कृषि विकास योजना तैयार करेगी। इसमें आगामी पांच साल की जरूरतों का आकलन किया जाएगा और फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुसार योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। कृषि विकास योजना में गांव की कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, भूमि उपयोग, सिंचाई, बिजली सहित अन्य जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसके साथ ही गांव में अधोसंरचना, स्वच्छता, पेयजल की स्थिति की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जिस तरह से गेहूं, धान सहित अन्य फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि अन्य राज्यों को भी आपूर्ति कर रहा है, उसी तरह अब अन्य फसलों पर ध्यान दिया जाए। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। दरअसल, एक तरह की फसल लगातार लेने से उत्पादन तो प्रभावित होता है भूमि की क्षमता पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी कृषि में फसलचक्र परिवर्तन पर जोर दे रही है। इसे बढ़ावा देने के लिए गांवों में किसानों द्वारा की जा रही खेती की जानकारी लेकर कार्ययोजना बनाना जरूरी है।

57 हजार गांवों पर फोकस

कृषि विभाग ने तय किया है कि प्रदेश के सभी 56 हजार 806 गांवों की समग्र कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी। इसमें खेती से जुड़ी सभी जानकारियां साफ्टवेयर में दर्ज रहेंगी। सरकार इसके आधार पर ही आगामी पांच साल की कार्ययोजना तैयार करेगी। आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी इस तरह की कार्ययोजना बनाने की बात कही गई है।

दलहन उद्यानिकी फसलों पर जोर

प्रदेश सरकार चाहती है कि किसान परंपरागत कृषि की जगह अब उन फसलों पर अधिक ध्यान दें, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो। दलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ाने की कार्ययोजना विभाग तैयार कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि किसान उद्यानिकी फसलों पर ध्यान दें। इसके लिए विभिन्न योजनाओं में अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को उपज के प्रसंस्करण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र की कृषि अधोसंरचना निधि से इसके लिए राशि भी दिलाई जा रही है।

खेती को आसान बनाएगा फार्म-फार्म मशीनरी ऐप

खेती को आसान बनाएगा फार्म-फार्म मशीनरी ऐप

भोपाल। मौजूदा समय में बिना कृषि यंत्रों की मदद से खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मगर खेती के लिए कृषि यंत्र खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं है, इसलिए अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, अब किसान खेती के कार्यों के लिए कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं।

अब मोबाइल से कृषि यंत्र को किराए पर लेने का काम बहुत आसानी कर सकते हैं। अगर किसानों के आस-पास कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, तो एक ऐप से जुड़कर किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। किराए पर कृषि यंत्र लेने के लिए मोबाइल ऐप आपको बता दें कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसका नाम फार्म-फार्म मशीनरी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से खेती से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही किसान कृषि यंत्र जैसे- ट्रैक्टर, टिलर, रोटावेटर समेत तमाम मशीनरी किराए पर ले सकते हैं।

कैसे करें ऐप डाउनलोड

किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फार्म-फार्म मशीनरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से होगा। अगर किसान फार्म-फार्म मशीनरी ऐप यंत्र किराए पर लेना चाहते हैं, तो यूजर श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर मशीनरी किराए पर देना चाहते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसान के सामने भाषा चुनने का विकल्प आएगा, जिसमें आप अपनी पसंद भाषा का चुनाव कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों की बुकिंग मोबाइल से

फार्म-फार्म मशीनरी ऐप पर कृषि यंत्र और मशीनों की पूरी डिटेल और किराया भी देखा जा सकता है। किसान अपने हिसाब से कृषि यंत्र और मशीन का चुनाव कर लें। इसके बाद अपने मोबाइल से बुकिंग भी कर सकते हैं। बता दें कि इन कृषि यंत्रों और मशीनों का किराया सरकारी रेट के अनुसार होता है।

ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध

फार्म-फार्म मशीनरी ऐप 12 भाषाओं में मुहैया है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और एक पासवर्ड तैयार करना होगा। इस ऐप में किसान को अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि नाम, प्रदेश, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम आदि। इनके अलावा किसान को कृषि योग्य भूमि का ब्योरा भी भरना होगा। इन तमाम जानकारियों को दर्ज करने के बाद किसान किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं।

शिवपुरी: मूंगफली की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र रही करैरा मंडी आय में पिछड़ी

करैरा। एक समय जिले में सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी के रूप में विख्यात करैरा मंडी दिन नंबर दो मंडी के रूप में जानी जाने लगी है। एक समय सी ग्रेड की मंडी रही करैरा मंडी आज आय के मामले में काफी पिछड़ गई है। इस मंडी में मची लूट में दूसरे विभागों से आये मंडी सचिव कुछ नेता और शेष कर्मचारियों और व्यापारियों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते मंडी को डी ग्रेड से भी नीचे धकेल दिया है। पूर्व के वर्षों के आय के आंकड़े देखें तो मंडी आय में दुगनी और तिगुनी तक वृद्धि हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय में इसमें लगातार गिरावट आ रही है। किसी भी जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप न होने से यहां के कर्मचारी और सचिव अपने निजी हित साधने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर किसानों के लिए यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्थिति यह है कि मंडी में कोई किसान आता है तो उसे पीने का पानी भी यहां नहीं मिलता है। किसान को दुकान से खरीदकर पानी पीना पड़ता है। व्यापारी खुलेआम मंडी के गेट के बाहर ही माल खरीद रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाता है। ऐसा ही हाल दिनारा और सिरसौद की उपमंडी है। एसडीएम के रूप में अब डीसी शुक्ला ने पदभार संभाला है। यह देखना होगा कि प्रशासक के रूप में वे यहां की व्यवस्थाओं में क्या सुधार ला पाते हैं।

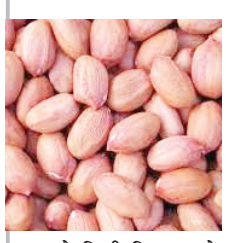

विक्रेता के नहीं आने पर मानी जाएगी मौन मंजूरी

मध्य प्रदेश में अब भूमि का नामांतरण होगा आसान

संवाददाता, भोपाल

भूमि के नामांतरण की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। जमीन बेचकर नामांतरण कराने में रुचि नहीं दिखाने वाले विक्रेताओं की वजह से परेशान होने वाले क्रेताओं को राहत देने और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत राजस्व न्यायालय से नोटिस तामील होने के बाद यदि विक्रेता नामांतरण के लिए उपस्थित नहीं होता है और आपत्ति भी दर्ज नहीं कराता है तो इसे उसकी मौन स्वीकृति माना जाएगा। इसके आधार पर न्यायालय नामांतरण संबंधी आदेश पारित कर सकेंगे। इसी तरह भूमि स्वामी की मृत्यु होने पर भूमि के नामांतरण के लिए वारिसों और सह-खातेदारों की अनुपस्थिति से भी प्रकरण लंबित नहीं रहेंगे। नोटिस जारी करने के बाद यदि आपत्ति न्यायालय को प्राप्त नहीं होती है तो नामांतरण आदेश पारित किए जाएंगे।

खरीदार होते हैं परेशान- दरअसल, राजस्व न्यायालय में ढाई लाख से ज्यादा नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं। राजस्व विभाग ने जब इनकी समीक्षा की तो यह बात सामने आई कि भूमि बेचने के बाद विक्रेता नामांतरण कराने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी वे नियत तारीख को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं। इससे जहां प्रकरण लंबित रह जाते हैं वहीं क्रेता भी परेशान होते हैं। जबकि नियमों में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में नोटिस देने के बाद यदि विक्रेता उपस्थित नहीं होता है और कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराता है तो फिर विक्रेता के पक्ष में नामांतरण कर दिया जाना चाहिए।

विक्रेता की मानी जाएगी मौन स्वीकृति

कलेक्टरों को विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में विक्रेता की मौन स्वीकृति मानते हुए उपलब्ध तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किए जा सकते हैं। इसी तरह भूमि स्वामी यदि जीवित रहते हुए खातों का विभाजन या नामांकन नहीं करा पाता है और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती है तो ऐसे मामलों में नामांतरण किया जा सकता है। विधिवत उद्घोषणा और पक्षकारों को सूचना पत्र तामील होने के बाद भी यदि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो आवेदक के पक्ष में आदेश जारी किए जा सकते हैं।

आमतौर पर भूमि विक्रय करने के बाद विक्रेता नामांतरण कराने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इससे अनावश्यक प्रकरण लंबित रहते हैं। जबकि, शासन की मंशा यह है कि अविवादित भूमि के नामांतरण में विलंब नहीं होना चाहिए। इसके मद्देनजर सभी कलेक्टरों को नामांतरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है कि वे विक्रेता के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर तय प्रक्रिया को अपनाकर नामांतरण कर सकते हैं।

ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयुक्त, भू-अभिलेख

हरी खाद अपनाइए,मिट्टी को स्वस्थ बनाइए

आशुतोष मिश्र
कृषि संकाय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि, चित्रकूट

भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं उसके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में सुधार लाने और उसमें मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए जो फसलें मिट्टी में दबा दी जाती हैं। उन्हे हरी खाद की फसलें कहते हैं। मिट्टी में दबी रहने के कारण इन फसलों के डंठल, पत्तियां आदि सड़कर खाद का रूप धारण कर लेती हैं। फसल खूब बढ़ने वाली तथा खूब पत्तियों वाली तथा शाखादार हों, ताकि प्रति हेक्टर अधिक से अधिक मात्रा में मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सके।

फ सल के वनस्पति भाग मुलायम हों, ताकि वे आसानी से सड़ सके। फलीदार पौधों की जड़ों में गांठे होती हैं जिनमें जीवाणु रहते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करते हैं। फलीदार फसलें मूलत: गहरी जड़ वाली होती हैं। अत: भूमि में काफी गहराई तक पोषक तत्व एकत्र हो जाते हैं। भारतवर्ष में गोबर की खाद का प्रयोग धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि गोबर के अन्य उपयोग भी हैं। ऐसे में हरी खाद ही है जिससे भूमि की जैव पदार्थ की कमी को दूर किया जा सकता है। हरी खाद के द्वारा प्रति हेक्टेयर 6.8 से 15 क्विंटल तक जीवांश भूमि में पहुंच जाता है। हरी खाद के उपयोग से मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे पानी, हवा और ताप धारण करने की शक्ति में पर्याप्त सुधार होता है। भारी मिट्टी को हल्की बनाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जा सकता है। हरी खाद से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। हरी खाद की फसलें भूमिक्षरण को रोकने में भी उपयोगी होती हैं। वैसे तो सभी फसलों में हरी खाद का प्रयोग लाभकारी है परन्तु धान, गेहूं, कपास, आलू, और तम्बाखू के लिए इसका प्रयोग विशेष उपयोगी है। हरी खाद के उपयोग से धान की पैदावार 30 से 75 पतिशत और गेहूं में 20-40 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। अनेक अनुसंधानों से पता चला है कि हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों में कुछ विशेष लक्षणों का होना जरूरी है। इन पौधों में तीव्र गति से वृद्धि हो, इनके पत्ते और डंठल मुलायम हों, इनकी जड़ें लंबी गहरी हों, इनके पौधों में पत्तियां अधिक हों, पौधे रेशेदार न हो, जिससे इनके सड़ने में अधिक समय न लगे। उस आधार पर सनई पौधे का पहला और ढेचां का दूसरा स्थान है। सनइ की फसल से 20 से 30 टन हरा पदार्थ प्राप्त होता है। इससे लगभग 85-125 किलाग्राम नाईट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करने की क्षमता रखती है। ढेंचा की फसल से 20-25 टन हरा पदार्थ तथा 85 से 105 किलाग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है। कृषि पंडित घाघ की कहावत किसानों में आज भी प्रचलित है।

सनई के डंठल खेत छिटावै।
तिनके लाभ चौगुना पावै।।

हरी खाद के लिए अन्य उपयोगी पौधे हैं, नील, मूंग, मटर मसूर, रिजका, लोबिया, आदि जाड़ों में हरी खाद देने के लिए बरसींग और रिजका की फसलें बहुत उपयोगी हैं। हरी खाद की बोवनी का समय इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए की उसे बढ़ने और फिर भूमि दबाए जाने पर सड़ने का पर्याप्त समय मिल जाए। खरीब के मौसम में धान की खेती के लिए अधिकांश हरी खादों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 25 जून के आसपास मानसून प्रारंभ होने के साथ ही खेतों को 2-3 बार जोतकर तैयार कर लेना चाहिए। सनई के बीज उपलब्ध हो तो 40 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में छिटक

कर पाटा चला देना चाहिए। बोने के लगभग 40 दिनों के अंदर ही इनके पौधे काफी बड़े लगभग तीन फीट के हो जाते हैं और फूलने लगते हैं। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इन पौधों को पलटने का सर्वोत्तम समय होता है। इसके लिए पहले पौधों का पाटा चलाकर गिरा देना चाहिए, तब मिट्टी पलटनें वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे पत्तियां व डंठल आदि मिट्टी में पूर्णत: ढक जाएं। उस समय खेत में मेढों को ठीक कर देना चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी खेत में रुका रहे और पौधे मिट्टी में दबकर सड़ जाए एवं खाद के रूप में बदल जाए। यदि उस समय खेत में नमी कम हो और वर्षा की संभावना न हो, तो सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि सड़ने का कार्य शीघ्र पूरा हो सके। नमी युक्त मिट्टी में ढकी रहने पर 20-25 दिनों के अंदर फसल के सभी अंग मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार इन पौधों से प्रति हेक्टेयर 20-25 टन मात्रा तक की हरी खाद प्राप्त हो जाती है। किसानों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसलें अच्छी तरह से सड़ जाएं अन्यथा दीमक का प्रकोप बढ़ सकता है। हरी खाद के बीज के लिए स्थानीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यदि किसी कारण सनई और ढेंचा के बीज न प्राप्त हो सके तो मूंग या अन्य किसी फलीदार पौधे के बीजों का 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर सें खेतों में बोवनी कर सकते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा नाईट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। गहरी जड़ वाली हरी खाद की फसलें मृदा के निचली पर्तों से अपनी जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का शोषण करती हैं। तथा मृदा की ऊपरी सतह मे विच्छेदित होकर इन पोषक तत्वों को छोड़ देती हैं। जिनका शोषण अन्य पौधे सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। मृदा की संरचना को सुधारती है। यह मृदा जल के वाष्पीकरण को रोकती है। मृदा कटाव को रोकती हैं। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाती है। मृदा में वायु का आवागमन अच्छा होने लगता है। हरी खाद की फसल से मृदा मे मिलाया गया कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का साधन भी है। साथ सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी बढ़ती है। अम्लीय मृदा में हरी खाद वाली फसलें जोतने पर उनका पीएच मान बढ़ता है। जबकि क्षारीय में पीएच कम होकर उदासीन मृदा बन जाती है। मृदा ताप को नियंत्रित करती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न दोष कम हो जाते हैं। यदि हरी खाद उचित ढंग से न दी गई हो तथा मौसम ठीक न हो तो उसके निम्न हानिकारक परिणाम सामने आते हैं। वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में यदि वर्षा की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो खाद का विच्छेदन नहीं हो सकेगा। जिससे अगली फसल भी नमी के अभाव के कारण ठीक प्रकार से नहीं उग सकती। कभी-कभी हरी खाद में अनेक हानिकारक कीड़ें लग जाते हैं। जो अगली फसल पर आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हरी खाद के लिए कोमल तनों एवं पत्तियों वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर ही हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद की फलीदार फसल को सुपर फास्फेट के साथ खेत में जोतना अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। फॉस्फोरस की उपस्थित में जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थिति सूक्ष्म जीव अधिक नाईट्रोजन स्थरीकरण करते हैं। फसल की पलटाई उस समय करनी चाहिए जब फसल में फूल आने वाले हों।

लुप्त-सुप्त होती गौग्रास निकालने की परंपरा को पुनर्जीवित करने का अनुकूल समय

अखिलेश्वरानंद गिरि
अध्यक्ष (कार्यपरिषद) मप्र गौ-पालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड

महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरि ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि-मुझे मध्यप्रदेश शासन की ओर से मध्यप्रदेश गौ- संवर्द्धन बोर्ड का पुन: दायित्व दिया गया है। मैं गौ संवर्द्धन बोर्ड की संवैधानिक नियमावली के दायरे में और राज्य शासन के अधिकारों की परिधि में ही रहकर प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के दायित्वों का निर्वहन करने में सदैव तत्पर रहता हूं। मेरा यह मानना है कि शासन गौ-वंश संरक्षण और संवर्द्धन के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और संकल्पना के अनुरूप अपने हिस्से का कार्य करेगा।

प्रशासनिक अधिकारी तदनुरूप नीति और संकल्प के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं, किन्तु गौवंश रक्षा के लिए अकेले शासन के बल पर पर बेहतर कार्य करना कठिन है। जब तक जन सामान्य की भागीदारी न हो। हमें अपनी भारतीय परंपरा का विस्मरण नहीं करना है। गौपालन, गौ-वंश संरक्षण और गौ-सेवा भारत के प्रत्येक परिवार की स्वाभाविक और पारम्परिक अभिरुचि रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय कृषि में गौ-वंश का अभूतपूर्व योगदान रहा है। गायों से प्राप्त पञ्चगव्य मनुष्यों के आहार का (भोज्य में) सहज हिस्सा रहा है। इसीलिए भारतीय परिवारों में गौ- पालन, गौसेवा,गौचारण की प्रवृत्ति रही है। गौदुग्ध जितना सतयुग, त्रेता एवं द्वापरयुग में प्रासंगिक रहा है, आज भी गायों से प्राप्त होने वाला दूध,दही,मट्ठा,मक्खन,खोवा,घी उतना ही प्रासंगिक है। हम मनुष्यों के भोजन का ये हिस्सा है। इसीलिए भारतवर्ष में एक धारणा रही है यहां दूध-घी की नदियां बहती रही हैं। भारत के प्रत्येक हिंदू परिवारों एवं गौ प्रेमी परिवारों में प्रतिदिन गौग्रास के नाम पर एक रोटी निकाली जाती थी। हम यह मानते हैं कि-एक रोटी से गाय का पेट नहीं भरा जा सकता। उसकी भूख नहीं मिटायी जा सकती, किन्तु हम भारतीय परिवारों का यह रोटी निकालने का आचरण एक सिंबल हम संवेदनशील भारतीयों का सात्विक आचरण का प्रतीक था। हमारे भारतीय ऋषि-मुनियों ने अपने ग्रंथों में उल्लेखित किया है कि इस पृथ्वी के सात धारक तत्वों में गाय (गौ वंश) प्रथम भूमिका में है।

गोभिर्विप्रैश्चवेदैश्च सतीभि: सत्यवादिभि:।
अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही।।

उपर्युक्त भावों के आश्रय से मेरे स्वर से जो

मुखरित होना चाहता है वह तथ्य यह है कि-जब गाय (संपूर्ण गौवंश) की प्रासंगिकता व उपयोगिता आज भी प्राचीन काल की भांति ही बनी हुई है तो गौपालन की स्वाभाविक प्रवृत्ति या पारम्परिक अभिरुचि से विरक्ति (उदासीनता) क्यों? हमारा प्रदेश (अपना मप्र) गायों (गौवंश) के पालन, संरक्षण, संवर्द्धन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। देश का सर्वाधिक गौवंश अपने प्रदेश में है। देश के किसी भी राज्य (प्रदेश)में इतना विशाल जंगल (95 हजार वर्ग किमी का वन्य परिक्षेत्र) नहीं है। शासन की गौ-पालन की स्पष्ट नीति, प्रदेश का मुखिया गौभक्त, गायों के प्रति संवेदनशील तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य, यहां का जैविक उत्पादन एवं उसकी मांग अनेक प्रदेशों में गायों एवं संपूर्ण गोवंश के रक्षण का सशक्त कानून राज्य में इतनी संभावनाओं के रहते हम आमजन गौ पालन के प्रति उदासीन और लापरवाह क्यों? आएं! हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि-हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर गौवंश के रक्षण का कार्य करेंगे, गौवंश के लिए गौग्रास की परम्परा को पुनर्जीवित करेंगे। हमारा प्रदेश सवा सात करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है। अगर एक करोड़ व्यक्ति भी प्रतिदिन गौग्रास के निमित्त 10 (दस रुपया मात्र)गुल्लक में डालेंगे तो वर्ष में 3650 (तीन हजार छह सौ पचास करोड़ की राशि संकलित होगी। यह राशि हम गौपाष्टमी के दिन अपने ग्राम की निकटतम गौशाला में समर्पित करेंगे। हम द्वापरयुग में स्थापित अपने पारम्परिक पर्व गौवर्धन पूजा और गौपाष्टमी को नवाचार विधि में ढ़ालकर उसे आधुनिक और युगानुकूल आकार देकर गौवंश को केंद्रित कर मध्यप्रदेश को स्वर्णिम राज्य की ओर अग्रसर करें।

पशुओं के चारे पर जीएसटी स्पष्टीकरण से विवाद संभव

इंदिवजल धस्माना

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद शराब उद्योग अवशिष्ट उत्पादों से बने पशुओं के चारे, खनिज अधिकार, यूपीएस इनवर्टर व एक्सटर्नल बैटरी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को लेकर विवाद हो सकता है। राजस्व विभाग के तहत आने वाले कर शोध इकाई (टीआरयू) की ओर से बुधवार को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि शराब उद्योग द्वारा इस्तेमाल होने वाले गन्ने और मक्के, मोलैसिस से बनने वाले ड्रायड डिस्टिलर्स ग्रेन विद सॉल्यूबल (डीडीजीएस) पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। यह स्पष्टीकरण जीएसटी परिषद की लखनऊ में हुई बैठक के मुताबिक जारी किया गया है। एएमआरजी ऐंड एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि शराब उद्योग जो अवशिष्ट निकालता है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस कचरे को नदी में छोड़ने पर रोक लगा दी है। इन निर्देशों का पालन करने के लिए शराब कंपनियों ने कचरे का निपटान शुरू किया और इसे डीडीजीएस में बदला, जिसे जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोहन ने कहा कि अन्य अवशिष्ट पर कर लगता है, जबकि जानवरों का चारा अलग श्रेणी में आता है और उस पर कोई कर नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि डीडीजीएस को कचरे के रूप में देखना गलत है। इसके अलावा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस इनवर्टर पर 18 प्रतिशत और एक्सटर्नल बैटरी पर 28 प्रतिशत कर होगा। ईवाई में टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि उद्योग आगे और स्पष्टीकरण चाहेगा, क्योंकि इसकी अलग कीमत नहीं होती और दोनों वस्तुओं का एक ही मूल्य होता है। टीआरयू में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खनिजों के अन्वेषण पर राज्य सरकारों की रायल्टी पर 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 तक 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं 1 जनवरी, 2019 से दरों में पहले ही संशोधन कर दिया गया है और इसे 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया है। रस्तोगी ने कहा कि यह स्पष्टीकरण न्यायिक जांच के दायरे में होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मसला यह बना हुआ है कि अगर कोई वैधानिक भुगतान है, तो क्या वह कर के दायरे में आएगा।

उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को घटा, कैस बढ़ेगी 2022 तक आय

किसानों को न सब्सिडी मिली, न ही खर्च कर पाए फंड

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में सरकार उद्यानिकी फसलों का बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के लिए उद्यानिकी फसलों की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। दरअसल, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी न तो किसानों का सब्सिडी दे पा रहे हैं और न ही फंड खर्च कर पा रहे हैं।

प्रदेश में आम, संतरा, अमरुद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित फूलों की खेती जैसे कट फ्लॉवर, बल्बस तथा लूज फ्लॉवर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इन फसलों की खेती करने वाले करीब 5000 किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी देने का टारगेट तय किया गया था, लेकिन फायदा 400 को भी नहीं हुआ है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया था, लेकिन आज तक न तो फसलों का उत्पाद बढ़ा और न ही आय बढ़ी। इसके पीछे उद्यानिकी विभाग के अफसरों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह बनी है।

किसान नहीं बढ़ा पाए उत्पादन

विदिशा निवासी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने 11 एकड़ में मसाला उत्पादन से जुड़ी फसलें लगाई थीं। सरकारी सहायता यानि सब्सिडी लेने के लिए आवेदन भी किया, लेकिन मेरी फसल का उत्पादन बढ़ा न आय में दोगुनी वृद्धि हुई। सरकार से सब्सीडी भी नहीं मिली। किसान अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें उद्यानिकी से संबंधित किसी योजना की जानकारी ही नहीं है। यह हाल अकेले किसान विनोद और अनूप के साथ नहीं है बल्कि प्रदेश के हजारों किसान पांच साल में अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाए और न ही आय में बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बढ़ती महंगाई से उनकी कमर और टूट रही है।

न प्रशिक्षण मिला, न जानकारी

एकीकृत बागवानी विकास के तहत योजना के लिए 40 जिलों में विशेष फोकस किया जाना था। विभाग के अनुसार भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खंडवा, मंडला, डिंडोरी, बुरहानुपर, बड़वानी, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, अशोकनगर, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया तथा आगर-मालवा में किसानों को प्रशिक्षण देकर इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाना था। लेकिन न तो किसानों का प्रशिक्षण मिला और न ही उन्हें योजना के बारे में जानकारी है।

फंड का उपयोग की नहीं हो पाया

एक तरफ किसान सब्सिडी की आस लगाए बैठे हैं वहीं दूसरी तरफ उद्यानिकी विभाग के भी आंकड़े बताते हैं कि मेन में एकीकृत बागवानी विकास को लेकर केंद्र से मिलने वाले फंड का उपयोग उद्यानिकी विभाग नहीं कर पा रहा है। इसके तहत प्रदेश में आम, संतरा, अमरुद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित पुष्प की खेती जैसे कट फ्लॉवर, बल्बस तथा लूज फ्लॉवर का उत्पादन दोगुना किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार से 60 फीसदी और राज्य से 40 फीसदी अंश राशि खर्च की जाती है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बीते 5 सालों में 337 करोड़ रुपए का आवंटन मप्र को मिला था, लेकिन इसमें से उद्यानिकी विभाग सिर्फ 169 करोड़ रुपए ही खर्च कर सका है। यदि टारगेट के हिसाब से किसानों को लाभ दिया जाता तो हर साल 4 से 5 हजार किसानों को फायदा मिलता।

पाताल में पानी...पांच साल में भू-जल स्तर सबसे नीचे

पाताल में पानी...पांच साल में भू-जल स्तर सबसे नीचे

संवाददाता, उज्जैन

अक्टूबर के महीने में शहर के कुओं में अमूमन दो-ढाई मीटर नीचे पानी मिल जाता था, पर इस साल 7 मीटर नीचे जाने पर भी नहीं मिल रहा। वजह, अनियोजित शहरीकरण, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और भूजल पुनर्भरण न होने से पानी पाताल में चले जाना है। अब यदि ग्रीष्मकाल में बोरिंग सूख गए तो आधी आबादी को जल संकट भोगना पड़ सकता है।

मालूम हो कि खेती की, बोरवेल के पानी पर बड़ी निर्भरता और आधी आबादी की पानी की जरूरते दो दशकों से भूमिगत पानी से ही पूरी हो रही है। इन दो दशकों में बारिश के पानी को सहेजने, भूजल पुनर्भरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हां, शिप्रा नदी पर नए बांध निर्माण की परियोजना, 140 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अनिवार्यता के नियम जरूर बनाए गए, पर नियमों का पालन हुआ और परियोजना धरातल पर आकार ले पाई। नियम कागजी खानापूर्ति तक सीमित होकर रह गए और परियोजनाएं कागजों के पुलिंदे में बंद होकर रह गई है।

यह भी दिक्कत- बारिश का पानी धरती में उतराने को 150 से ज्यादा कालोनियों में कच्चा मिट्टी का स्थान भी नहीं छोड़ा। एक नाली से दूसरी नाली को सटाकर हर जगह सड़क बना दी। इससे बारिश का सारा पानी सड़क से नालियों में उतर शहर के बाहर नदी में जा मिला। नतीजनत आधे शहर में भूजल पुनर्भरण नहीं हो पाया। जानकारों का कहना है कि भूमिगत जल समेत तमाम जल संसाधनों के ठीक प्रबंधन से स्थिति को सुधारा जा सकता है, पर शासन-प्रशासन के रवैये से इस बात की फिलहाल कोई सूरत दिखाई नहीं देती। जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिन पानी सब सून होगा।

इस साल पर्याप्त बारिश न होने से सूखे रह गए 20 तालाब

इस साल पर्याप्त बारिश न होने से 52 में से 20 तालाब सूखे रह गए। 15 जून से 30 सितंबर तक पूरे वर्षाकाल में केवल 708 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। ये औसत 906 मिलीमीटर से काफी कम है। हालांकि 30 सितंबर के बाद भी यदा-कदा वर्षा का दौर जारी है, मगर कोटा अब भी पूरा नहीं हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 52 में से 20 तालाब सूखे हैं। साहिबखेड़ी, अरनिया तालाब अपनी पूर्ण क्षमता से भरा है। इंदौख बेराज 91 फीसद भरा है। उंडासा तालाब 51 फीसद भरा है।

आधी आबादी की जल आपूर्ति का मुख्य केंद्र गंभीर बांध लबालब

शहर की आधी आबादी की जल आपूर्ति का मुख्य केंद्र, गंभीर बांध अभी लबालब भरा है। 2250 मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) जल संग्रहण क्षमता वाले बांध में अभी 2200 से एमसीएफटी से अधिक पानी है। इतना कि शहर के 60 हजार परिवारों की दैनिक जरूरत 8 एमसीएफटी प्रतिदिन के हिसाब से 275 दिन शहर में नियमित सप्लाई किया जा सकता है। अभी शिप्रा नदी भी लबालब भरी है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, संकट के समय उज्जैन के लिए नर्मदा का जल आरक्षित करने को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को पत्र भी भेज चुके हैं। लिहाजा यह तय है कि निगम से संबद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से नल कनेक्शन पाए लोगों को पानी की परेशानी नहीं आएगी।

देवास रोड की कालोनियों में लगभग हर घर में बोरिंग

इंदौर-देवास रोड से लगी कालोनियों में लगभग हर घर में बोरिंग है। अधिक संख्या में बोरिंग होने से यहां भूमिगत जल स्तर काफी नीचे है। हर साल ग्रीष्मकाल में आधे से ज्यादा घरों में बोरिंग से पानी निकलना बंद हो जाता है। ऐसे में वे पड़ोसी या नगर निगम के टेंकर जलापूर्ति व्यवस्था पर निर्भर हो जाते हैं। कई बार कालोनीवासियों ने अपने क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की पाइपलाइन बिछाने को आवाज भी उठाई, पर अब तक पाइपलाइन नहीं बिछ पाई।

रबी सीजन की बोवनी में जुटे किसान

तीन लाख 30 हजार हेक्टेयर में होगी बोवनी

संवाददाता, नर्मदापुरम

जिले में इस बार 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर में रबी सीजन की बोवनी का अनुमानित प्लान बनाया गया है। क्षेत्र में अपेक्षाकृत बारिश होने से जमीनी जल स्तर ठीक ही है। इसीलिए इस बार गेहूं का रकबा बीते वर्ष से कुछ कम करके चना का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग भी चाह रहा है कि गेहूं का रकबा बीते वर्ष से कम हो। जिससे किसानों और कृषि विभाग का ध्यान इस बार फिर चने की बोवनी की और ही ज्यादा है। इसके साथ ही मसूर, मटर, राई-सरसों, गन्ना, अलसी, रबी मक्का आदि की भी बोवनी होगी। क्षेत्र के किसान रबी मौसम की बोवनी की तैयारी में जुटने लगे हैं। इस पखवाड़े के अंत तक बोवनी तेजी से शुरू हो जाएगी।

दो लाख 85 हजार हेक्टेयर में होगी गेहूं की बोवनी: जिले में इस बार 2 लाख 85 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी होने का अनुमान कृषि विभाग लगा रहा है। बीते वर्ष 2 लाख 98 हजार हेक्टेयर में तथा उससे पूर्व 2019-20 में 3 लाख 8 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। उस तुलना में इस बार तीन वर्ष में सबसे कम गेहूं बोने का प्लान है।

शुरू हो गई बोवनी की तैयारी

इस बार मानसून के देरी से आने के कारण कुछ किसानों ने धान लगाने से वंचित रहने पर अपने खेत खाली रखे हैं, जो अब जल्द ही रबी की बोवनी करना चाह रहे हैं। ऐसे किसान अगले सप्ताह से रबी मौसम के चने की बोवनी शुरू कर देंगे।

- इस बार जिल में तीन लाख 30 हजार हेक्टेयर में रबी मौसम की फसलें ली जाना है। किसानों का ज्यादा ध्यान चना की ओर ब? रहा है। सबसे ज्यादा बोवनी गेहूं की रहेगी। तवा बांध भरा है, इसलिए गेहूं को पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

जेआर हेड़ाउ, उप संचालक कृषि

चना की बोवनी पर भी ज्यादा जोर: बीते वर्ष चना की पैदावार और भाव अच्छे मिलने से इस बार भी चना की बोवनी पर ज्यादा जोर रहेगा। इस बार चना की बोवनी जिले में 35 हजार हेक्टेयर में की जाने की तैयारी है। बीते वर्ष 24 हजार में ही हुई थी। उससे पूर्व 2019-20 में सिर्फ 13 हजार हेक्टेयर में ही हुई थी।

चना की बोवनी में ज्यादा फायदा: किसान तथा कृषि विभाग का मानना है कि गेहूं की अपेक्षा चना की बोवनी करने में ज्यादा फायदा है।

बांध के पानी की बचत होगी

किसान नरेंद्र पटेल ने कहा कि चना की बोवनी करने से एक ही बार पानी दिया जाता है, जिससे तवा बांध में पानी की बचत हो जाती है जो मूंग के लिए काम आ जाता है। इस वर्ष मूंग ने किसानों को 10 अरब रुपए दिलाए हैं इसलिए भी किसान मूंग की बोवनी समय पर करना चाहेंगे।

सरकार भी किसानों के लिए खेती के कार्यों को आसान बनाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही

रोपाई को आसान बनाएगी मैकेनिकल प्लांटर मशीन

भोपाल। खेती-बाड़ी के सभी कार्यों जैसे खेत की जुताई, फसल की बोवनी, सिंचाई, कटाई, मड़ाई और भंडारण आदि में कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि मौजूदा समय में किसान अपनी फसलों की पैदावार अच्छी और अधिक प्राप्त कर रहे हैं। आज किसान खेती में नई-नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। वहीं, सरकार भी किसानों के लिए खेती के कार्यों को आसान बनाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है। इसी क्रम में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई मेकैनिकल प्लांटर मशीन लांच की है। इस मशीन के विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्व-चलित प्लांटर मशीन से किसानों को श्रम की समस्या से आजादी मिलेगी।

एक दिन में होगी 3-4 एकड़ रोपाई

मैकेनिकल प्लांटर मशीन का उपयोग रोपाई के कार्य में किया जाता है। इससे प्रतिदिन 3 से 4 एकड़ खेत में रोपाई की जा सकती है। इस प्लांटर मशीन से चटाई प्रकार की नर्सरी को पॉलिथीन शीट पर या ट्रे में उगाया जाता है। इसके बाद फ्रेम को पॉलिथीन शीट पर रख दिया जाता है फिर इसके किनारों में मिट्टी डाल दी जाती है। इसके बाद नर्सरी सीडर द्वारा बीज को फ्रेम में रख दिया जाता है।

किसानों की पसंद बनी तकनीक

मोगा जिले के बद्दुवाल गांव में चटाई प्रकार की नर्सरी उगाने एवं यांत्रिक तरीके से रोपण प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद ही किसान आईसीएआर द्वारा लॉन्च की गई तकनीक को अपना रहे है। वर्तमान समय में मोगा क्षेत्र के कई किसान इस कृषि यंत्र से प्रभावित होकर खरीद कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान भाई मशीन को किराए पर देकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। मेकैनिकल प्लांटर मशीन खेती के लिए काफी लाभदायक है। इससे किसान भाई अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।

-बोवनी के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना उपयुक्त

किसानों को मालामाल करेगी लहसुन की खेती

लहसुन की फसल 5-6 माह में होती है पककर तैयार

संवाददाता, भोपाल

परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। लहसुन की खेती एक ऐसी फसल है, जिसकी खेती कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम इसकी खेती में निवेश की बात करें, तो लहसुन के बीज की कीमत एवं इसकी खेती में लगभग एक लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निवेश करना होता है। लहसुन की खेती से आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी साथ ही कम निवेश में लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा सकते हैं। लहसुन की खेती के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना उचित माना जाता है। लहसुन की खेती मेड़ बनाकर की जाती है। मिट्टी में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। बोवनी

10 सेमी की दूरी पर की जाती है। लहसुन की फसल 5-6 महीने में पककर तैयार हो जाती है। लहसुन की खेती उसकी कलियों द्वारा की जाती है।

कितना होगा मुनाफा- जिसमें एक हेक्टेयर से आपको औसतन 130 क्विंटल लहसुन की पैदावार मिल सकती है। वहीं बात करें इसके भाव की तो बाजार में इसका भाव 35- 50 रुपए प्रति किलो है।

कितनी होती है पैदावार

लहसुन की खेती में पैदावार की बात करें, तो एक हेक्टेयर में 120-150 क्विंटल लहसुन की उपज प्राप्त होती है। वहीं इसकी बोवनी की प्रक्रिया की बात करें तो एक हेक्टेयर खेत में करीब 5 क्विंटल तक लहसुन की कलियां लगायी जाती है। लहसुन के बीज आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं।

जैविक खेती को बढ़ावा देने बांटे गए सब्जियों के बीज

मुरैना। मुरैना और श्योपुर जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फलदार 71 हजार पौधों के रोपण व सब्जियों के बीज वितरण के साथ हुआ। पखवाड़े के तहत केंद्र व राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं व भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए। समापन कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल जुड़े केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इन बीज वितरण का उद्देश्य ग्रामीण गरीब को जैविक खेती के लिए जागरूक करना है, ताकि वो अपने निवास के आसपास ही जैविक सब्जियां उगा सकें, जिससे उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिलें। गत वर्ष भी बड़े पैमाने पर सब्जियों के बीज वितरित किए गए थे। इस पूरे कार्यक्रम में इफ्को का भी सहयोग रहा। उन्होंने दोनों कलेक्टरों से इफ्को द्वारा विकसित नैनो यूरिया का ड्रोन द्वारा जिलों के खेतों में छिड़काव करवाने को कहा, ताकि किसानों को भी इससे मदद और प्रोत्साहन मिले। साथ ही पर्यावरण की रक्षा होगी, पानी की बचत होगी, किसानों को कम लागत आएगी व खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने से उत्पादकता बढ़ेगी।

ड्रोन से नैनो यूरिया का किया जाएगा छिड़काव

-खेती की तरक्की में आधुनिक ज्ञान के प्रसार जरूरी

खेती का ज्ञान बढ़ाने विवि की भागीदारी सबसे अहम

संवाददाता, जबलपुर

खेती की तरक्की में आधुनिक ज्ञान के प्रसार जरूरी है। इसके लिए कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका अहम है। सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। इसके लिए डिजीटल कृषि मिशन शुरू किया गया है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कही। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 58वें स्थापना दिवस पर बोले रहे थे। इस दौरान विवि के विज्ञानी, प्रोफेसर्स, विद्यार्थियों से लेकर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खेती के साथ ग्रामीण परिवेश में भी समृद्धि आनी चाहिए, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों को स्वंतत्रा देने के लिए कानूनी बंदिशों को तोड़ा है और किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर देशभर में कृषि विवि में नई शिक्षा नीति के परिवेक्ष्य में कृषि शिक्षा नीति लागू की जाएगी। आईसीएआर ने इस संबंध में

तैयारी कर ली है और हाल ही में इसके डाक्यूमेंट का विमोचन भी किया गया है। सम्मानित हुए उत्कृष्ट कृषक, शिक्षक विवि के कुलपति प्रो. प्रदीप बिसेन ने स्वागत भाषण दिया और विभिन्न पुरस्कारों को का वितरण किया। कुलपति ने कहा कि विवि ने न सिर्फ अनुसंधान, बल्कि कृषि शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहां हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। समारोह के दौरान आदिवासी महिला कृषक के तौर पर तीन महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन्हें वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी, मंडला और शहडोल में सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित शर्मा ने किया।

महिला किसानों के लिए खास मशीन

किसानों के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, खेती बनेगी लाभ का धंधा

संवाददाता, भोपाल

कृषि क्षेत्र में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई कृषि यंत्रों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि महिला किसान इनका उपयोग आसानी से कर सकें। इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है। कहा जाता है कि खेतों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, इसलिए देश के वैज्ञानिकों ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कृषि यंत्र बनाए हैं, जो उनके लिए बहुत आरामदायक और सुविधाजनक हैं।

एक नजर कृषि यंत्रों पर

नवीन डिबलर: खेत में छोटे स्तर पर मक्का, सोयाबीन, मटर जैसे मध्यम एवं बड़े बीजों की कतार में बुवाई करने के लिए नवीन डिबलर का उपयोग किया जाता है। इसमें पंजे के आकार का बीज गिराने का यंत्र, सेल की तरह मीटर मशीन, रोलर और लीवर टाइप पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एवं बीज गिराने के लिए एक बीज बॉक्स लगा होता है।

सीआईएई सीड ड्रिल: इस कृषि यंत्र का उपयोग गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चना, और अरहर के बीजों को एक पंक्ति में बोने के लिए होता है। इसमें हैंडल, हॉपर, एक ग्राउंड व्हील, एक फ्लुटेड रोलर और ड्रिल खींचने के लिए एक हुक लगता होता है। इसे चेन और स्पॉकेट के जरिए ग्राउंड व्हील शाफ्ट से संचालित किया जाता है।

पावर टिलर: पावर टिलर के उपयोग से श्रमिक लागत और कड़ी मेहनत में कमी लाई जा सकती हैं। इसके साथ ही बीज की बचत की जा सकती है। ध्यान रहे कि इस कृषि यंत्र का उपयोग करने के लिए खेत में कम से कम 25 से 50 मिमी पानी होना चाहिए। इसकी मदद से एक साथ दो पंक्तियों में धान रोपण किया जा सकता है।

गन्ना बड चिपर: इस कृषि यंत्र का उपयोग गन्ने के गठान को अलग करने के लिए किया जाता है। इस कृषि यंत्र में अर्धगोलाकार चाकू हस्त चलित लीवर में लगा होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गन्ने को प्लेटफार्म पर रखा जाता है फिर चाकू को हस्तचलित लीवर से दबाकर 180 डिग्री पर घुमाया जाता है। इसके बाद गन्ने से उसकी गठान अलग हो जाती है, जो सीधे खेत में बोने के लिए उपयोग की जा सकती है। इस कृषि यंत्र की मदद से गन्ने की बर्बादी कम होती है।

पहाड़ी पर बने सिद्ध बाबा मंदिर को दार्शनिक स्थल में परिवर्तित कर लॉकडाउन का सदपयोग किया स्वयंसेवियों ने

मरुस्थल पर पहुंचाया पानी, वीराने को रमणीक स्थल में किया तब्दील

मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद-चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय..जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि की यह पंक्तियां विजयपुर के उन स्वयंसेवियो पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने एक हजार फीट की ऊंचाई पर न सिर्फ पानी पहुंचा दिया, बल्कि वीरान रहने वाले इस पहाड़ी मरुस्थल को गुलिस्ता बना दिया है।

संवाददाता, श्योपुर

हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मंदिर की जो एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। लोगों की आस्था का प्रतीक इस मंदिर पर भक्त मन्नत-मुरादें मांगने जाते तो है, लेकिन इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर प्यास से व्याकुल हो जाने की वजह से कम लोग ही मंदिर पर जा पाते थे, लेकिन कुछ स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की बदौलत अब मरुस्थल समझा जाने वाला यह स्थल गुलजार हो गया है। मंदिर प्रांगण और आसपास कई प्रकार के छायादार व फलदार पौधे रोपे गए हैं, जहां लोग जाने में कई बार विचार करते थे आज वहां जाकर लोग पिकनिक मना रहे हैं।

वैसे तो पहाड़िया भी हरी भरी होती हैं। पहाड़ियों पर खूब पेड़ लगे होते हैं, लेकिन पेड़ों के मामले में शायद विजयपुर की यह पहाड़ी शायद अभिशप्त ही है। यहां इक्के-दुक्के पेड़ दिखाई देते हैं। मंदिर के आसपास चारों ओर पथरीला मैदान बड़े-बड़े पत्थर जो पहाड़ की चट्टाने हैं, ही दिखाई देती है। इन्हीं चट्टानों के बीच विजयपुर के स्वयंसेवियों ने पौधें रोपकर बहार ला दी है। शुरुआत में इन स्वयंसेवियो के जुनून को लोग पागलपन भी कहने से नहीं चूकते थे। लोग इन्हें पहाड़ी पर पौधें रोपने और वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाकर सिंचाई करने को प्रकृति के विपरीत काम बनाते थे। लोग पत्थर में कभी पौधा नहीं लग सकता कहकर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन इन्होंने मन में जो ठानी उसे करके भी दिखाया। आज सिद्ध बाबा के आसपास एक हजार के करीब पीपल आंवला जामुन सिरस, नीम, बेलपत्र आदि के पौधे लहलहा रहे हैं। इस सत्कर्म में रामनिवास गौड़, संजय मंगल, आसाराम सोनी, अनूप मंगल, पवन बंसल, धन्नू गोयल, सुरेंद्र सोनी, बंटी कुशवाह, उदय भान रावत, अंशुमन रावत, नितिन, मनोज उदैया, बंटी हुल्लपुरिया, मुकेश गर्ग, प्रदीप गर्ग, स्वीटी मित्तल आदि स्वयंसेवीओ का सराहनीय योगदान रहा है।

एक हजार फीट की ऊंचाई पर पानी पहुंचाकर बनाया पर्यटक स्थल

स्वयंसेवियों ने पौधे लगाकर टैंकरों के माध्यम से पौधों की सिंचाई तो कर दी, लेकिन वहां दर्शनार्थियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था चुनौती का काम थी। इस काम को भी स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने बोर करा कर मंदिर पर एक हजार फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचा कर पूरा किया। मंदिर में चबूतरा निर्माण कराकर दर्शनार्थियों के बैठने आराम करने और भोजन बनाने, भोजन करने की सुविधा के साथ मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। मंदिर के चारों ओर तारफैंसी बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है, ताकि मंदिर पर्यटक स्थल की तरह दिखाई दे।

आश्चर्य से भरी सिद्ध बाबा की गुफा

मन पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा रहस्यमई होकर कई किवदंती अपने साथ लिए हुए हैं। लोगों का कहना है कि यह गुफा धौरेट सरकार पर निकलती है। हालांकि गुफा में अंधेरा अधिक रहने और कीड़े का डर होने की वजह से लोग आगे नहीं जा पाते हैं। गुफा में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, लेकिन यह गुफा दर्शनार्थियों की अभी भी पहली पसंद बनी हुई है

पत्थर के घर बनाकर मांगते हैं मन्नत-मुरादें

मंदिर पर आने वाले लोग मैदान में खुले में पत्थर के छोटे छोटे से घर बनाकर मन्नत मुरादें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर बनाकर मांगी गई मन्नत सिद्ध बाबा जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि खुले पठार में पहाड़ पर दूर-दूर तक बच्चों के खिलौने जैसे घर बड़ी संख्या में बने हुए दिखाई पड़ते हैं।

24 गांवों में से 22 का मिला रिकॉर्ड, दो का रिकॉर्ड नहीं मिलने से अटका नोटिफिकेशन

25 साल गुजरे, अभी रेवन्यू गांव ही हैं कूनो के अंदर के वीरान गांव

विशेष संवाददाता, श्योपुर

श्योपुर के लोगों के लिए दिव्य स्वप्न बनी कूनो सेंचुरी के पूर्ण होने में किस कदर लालफीताशाही हावी है कि 25 साल गुजरने के बाद भी कूनो सेंचुरी के अंदर वीरान 24 गांव आज भी रेवन्यू गांव बने हुए हैं। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो यह अभी भी वन क्षेत्र नहीं हैं। क्योंकि इन गांवों का नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण वन विभाग इन्हें अपने स्वामित्व में नहीं मानते हुए जंगल विकसित करने का कार्य नहीं कर पा रहा है। नोटिफिकेशन जारी न होने के पीछे कारण 2 गांवों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग से न मिलना बताया जा रहा है।

खास बात यह है कि कूनो वन मंडल के अधिकारी इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन को पत्र भी लिख चुका है। इसके बाद भी जिला प्रशासन दो गांवों का राजस्व रिकॉड कूनो वन मंडल को उपलब्ध नहीं करा सका है। जिसकारण विस्थापित हो चुके 24 गांवों का नोटिफिकेशन का काम अभी तक अटका पड़ा है। यहां बता दें कि श्योपुर जिले में एशियाई सिंहों के नए घर के रूप में संरक्षित किए गए कूनो के जंगल में वर्ष 1996 में 24 गांव विस्थापित किए गए थे। एशियाई सिंहो को यहां बसाने के लिए

श्योपुर जिले के विजयपुर और कराहल विकासखंड के 24 गांवों के 1545 परिवारों को विस्थापित करते हुए दूसरी जगह बसाया गया था। जिस पर 4 करोड़ 67 लाख की राशि खर्च की गई। 25 साल का समय बीतने के बाद अब कूनो के अंदर के ये गांव वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गए है, लेकिन इनका विधिवत नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका है। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी गांवों का राजस्व रिकॉर्ड मिलने के बाद ही शासन स्तर से इन गांवों का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद ही विस्थापित गांव विधिवत रूप से कूनो सेंचुरी के होगे और तभी इन गांवों की जगह पर जंगल विकसित करने संबंधी गतिविधियों पर शासन राशि खर्च कर सकेगा।

इन गांवों का हुआ विस्थापन- नेशनल पार्क का दर्जा हांसिल कर चुके श्योपुर के कूनों अभ्यारण्य को बसाने के लिए जिले के जिन 24 गांवों का विस्थापन किया गया है, उनमें पालपुर, जाखौदा, पैरा, पांडरी, लादर, दुर्रेडी, बरेंण्ड, खलाई, पारोंद, चक पारोंद, मसावनी, चक मसावनी, बावनपुर, बसंतपुरा, खैरा, पिपरवाड़ा, खजूरी खुर्द, खजूरी कलां, रामपुर, राजपुरा, अहिरवानी, नयागांव, टोंगरा, सिलपुरा, शामिल हैं। 25 साल की अवधि गुजरने के बाद राजस्व विभाग कूनो वन मंडल को अभी तक 22 गांवों का राजस्व रिकॉर्ड ही ढूंढ़कर सौंप सका है। लेकिन दो गांवों का राजस्व रिकॉर्ड देना शेष रह गया है। वन विभाग के सूत्र बताते हैं कि दो गांवों पिपरवाड़ा और खैरा गांव का रिकॉर्ड न मिलने के कारण ही 24 गांवों का नोटिफिकेशन का काम अटका है।

जनवरी तक टल गया चीतों का आना

कूनो में अफ्रीकी चीतों के आने का कार्यक्रम अगले साल जनवरी तक टल गया है। इसके पीछे कारण श्योपुर जिले में आई बाढ़ और अतिवृष्टि रही है। क्योंकि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण कूनो सेंचुरी में चीतों के बसाने को लेकर चल रही तैयारियां समय सीमा में कंपलीट नहीं हो सकी हैं। जिस कारण ही एक नंबवर को चीतों के कूनो में आने का कार्यक्रम टला है। बताया जा रहा है कि अब संभवत:अगले साल जनवरी में ही अफ्रीकी चीते कूनो सेंचुरी में आ पाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री राजी अब सिंधिया के सिग्नल का हो रहा इंतजार

श्योपुर का अमरूद विदेशों में भरेगा उड़ान

» जिले के अमरूद का स्वाद विदेशों व हवाई सफर में भी ले सकेंगे

» अब पल्प और जूस निकालने जर्मनी से मध्यप्रदेश आएगी मशीन

संवाददाता, श्योपुर

देशभर में कुपोषण के बदनाम मप्र का आदिवासी बहुल जिला श्योपुर के अमरूद का स्वाद विदेशों और हवाई सफर में भी ले सकेंगे। एक जिला-एक उत्पाद के तहत चुने गए अमरूद के उत्पादन को देखते हुए प्रशासन इसका पल्प, जूस और जैली बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है। पल्प (गूदा) निकालने वाली मशीन जर्मनी से आएगी। जिले की मिट्टी और वातावरण अमरूद की खेती के लिए मुफीद है।

जिले में अब तक 2820 किसान 1200 हेक्टेयर में अमरूद का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन इस साल 5 हजार किसानों को अमरूद का बाग लगाने के लिए तैयार किया गया है। जिले में अमरूद का पल्प निकालने के लिए अभी इसे छीलकर व टुकड़ों में काटकर बहुत कम पानी के साथ एक मिक्सर में ब्लेंड किया जाता है। जर्मनी से मशीन लाने के लिए आजीविका मिशन ने मां रेवा वैदिक फूड कंपनी से अनुबंध किया है। कपंनी अमरूद के पल्प, जूस और जैली को देश और विदेश में सप्लाई करने लायक बनाने के लिए शुरुआत में टेक्निकल और मार्केटिंग की मदद करेगी।

यूनिट को शुरू करने का प्रयास

अमरूद की फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कराने के लिए 2 अक्टूबर को मां रेवा वैदिक फूड कंपनी के फाउंडर वारूस सिंह श्योपुर आए थे। मशीन लगाने के लिए शिवपुरी रोड स्थित बीआरसी भवन का निरीक्षण भी किया। प्रशासन हर हाल में यूनिट 1 नवंबर को मप्र स्थापना दिवस पर चालू करने का प्रयास कर रहा है।

» मप्र स्थापना दिवस पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने की तैयारी

» अमरूद के पल्प के साथ जैली व पाउडर भी किया जाएगा तैयार

30 लाख से तैयार होगी यूनिट

यूनिट तैयार करने की लागत करीब 30 लाख रुपये है। इन आधुनिक मशीनों से अमरूद का पल्प, जैली, जूस के साथ सूखा पाउडर भी तैयार किया जाएगा। जिसे लंबे समय तक स्टोर कर रखा जा सके। यूनिट में ट्रेंड फूड न्यूट्रिशियन (वैज्ञानिक)भी रखा जाएगा, जो पूरी टेस्टिंग कर स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के प्रोडेक्ट तैयार करवा सके। यह काम आदिवासी महिलाएं फूड न्यूट्रीशियन की देखरेख में करेंगी।

किस तरह अमरूद के पल्प, जैली, जूस और पाउडर को विश्व स्तरीय बनाया जा सके इसके लिए मां रेवा वैदिक फूड कंपनी की मदद ले रहे हैं। कंपनी फूड प्रोडक्ट को यूरोप, यूएस, हांकगांग सहित अन्य देशों में सप्लाई करती है। पल्प और जूस को देश में एयरलाइन में सप्लाई करने के लिए कृषि केंद्र मंत्री नरेंद सिंह तोमर से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में वह केंद्रीय उडडयन मंत्री ज्योरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे। विदेश में सप्लाई करने के लिए मां रेवा वैदिक फूड कंपनी मदद करेगी यूनिट में 200, 500, 1 लीटर और 5 लीटर के जार और पाउच में पैकिंग की जाएगी।
शिवम वर्मा, कलेक्टर, श्योपुर

जिले में वैसे तो अमरूद की किस्म बर्फानी गोला, इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, ग्वालियर-27 का उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रशासन थाई अमरूद के बाग तैयार करवा रहा है। हैथाई अमरूद के पौधे की खासियत है, कि इसे हल्की व पथरीली सफेद मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। पौध लगाने के बाद इसके रखरखाव का खर्च भी बेहत कम है। इस अमरूद का उत्पादन 12 माह में शुरू हो जाता है। थाई अमरूद में फाइबर, विटामिन सी और फोलिक एसिड भरपूर होता है।
डॉ. एसके मुदगल, डीपीएम
आजीविका मिशन

मध्य प्रदेश: सितंबर की बारिश से सड़ गईं उड़द, मूंग और तिल

सतना। कुछ दिन पहले तक जिस खेत में उड़द मूंग की फसल लहलहा रही थी, उसी खेत में भैंसों का झुंड चरने के लिए छोड़ दिया गया था। खेत के किनारे सड़क पर छाता तानकर खड़े किसान दद्दी पाल का खेत भी है और उन्हीं की भैंसें भी हैं। सितम्बर महीने के आखिर में हुई बारिश से सब बर्बाद हो गया है। 60 साल के दद्दी पाल कहते हैं कि मूंग और उड़द की कुछ फसल अभी भी खेत पर खड़ी है। कुछ काट कर घर ले आए हैं। जो फसल खेत पर खड़ी है उसमें दाना लगता है कम ही निकलेगा। बाकी जो घर लाए हैं उस से पांच-दस किलो दाना शायद निकल आएगा। इसलिए खेत पर खड़ी फसल में भैंसों को छोड़ दिया है। ताकि उन्हीं का भला हो जाए। दद्दी मप्र के सतना जिले में आने वाले गांव पोखरा के किसान हैं। पोखरा जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी है। उनके पास एक एकड़ जमीन है जिसमें कुछ भाग में उड़द और कुछ में मूंग की फसल बोई थी। कुछ में धान भी लगा रखा है। मूंग की फसल तो खेत पर खड़े-खड़े ही सड़ गई। 15 कुराई के खेत मे लगा रखी थी। इसी में उड़द भी है। वही बस घर तक जा सकी। इसलिए भैंसों को खेत में छोड़ दिया। अब बस धान है जिस पर भरोसा टिका है। सतना जिला के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के आंकड़ों पर भरोसा करें तो खरीफ सीजन 2021-22 में मूंग, उड़द और तिल की फसल की बोवनी का लक्ष्य शत-प्रतिशत से भी ज्यादा रहा।

लक्ष्य से ज्यादा बोवनी

सहायक संचालक (कृषि) आर के बागरी के अनुसार सतना जिले में मूंग की बावनी का लक्ष्य 2.534 हेक्टेयर रखा गया था। 27 सितंबर 2021 की स्थिति इस लक्ष्य की पूर्ति 2.600 हेक्टेयर है। जो कि 102.60 प्रतिशत है। इसी तरह उड़द का लक्ष्य 70.106 हेक्टेयर रखा गया था जिसमें अब तक 101.65 प्रतिशत पूर्ति हुई है। यानि कि 71.260 हेक्टेयर की पूर्ति हुई है। धान के लिए 249.680 हेक्टेयर का लक्ष्य था जिसमें 249.890 प्रतिशत की पूर्ति हुई है।

फसल को लग गए दीमक

उड़द मूंग की फसल के बाद बारिश का सबसे ज्यादा असर तिल की फसल पर पड़ा है। तिल में जहां दाने कम देखे गए वहीं काट कर रखी गई फसल में दीमक भी लग गए। उचेहरा तहसील की ग्राम पंचायत भर्री पंचायत के पूर्व सरपंच कैदी लाल कोल पेशे से किसान हैं। उनके पास इस समय 3 एकड़ खेती लायक जमीन है। इस जमीन में उड़द, मूंग और धान लगा रखा है। इनका भी हाल दद्दी जैसा ही है। बड़ी परेशानी यह है कि तिल की फसल में दीमक लग गए।

-जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि ने विकसित की तीन नई किस्म

चने की तीन नई प्रजातियां किसानों को बनाएंगी आत्मनिर्भर

-गर्म स्थानों में भी होगा चना और गेहूं की तरह होगी कटाई

संवाददाता, जबलपुर

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने चने की नई प्रजाति खोजी है। चने की जेजी-11, 14 व 24 को विकसित किया है। चने की ये तीनों फसलें गर्मी वाले स्थानों पर उगाई जा सकेगी। इसके पौधे लंबे होते हैं और इसे गेहूं की तरह हार्वेस्टर से काटा जा सकेगा। जेएनकेविवि द्वारा विकसित जेजी-11, 14 और 24 चने की फसल 60 सेमी ऊंचाई तक होगी। अभी सामान्य चने की फसल 20 सेमी ही होते हैं। जेएनकेविवि चना अनुसंधान की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनीता बब्बर के मुताबिक जेजी 24 प्रजाति की ऊंचाई 60 सेमी से अधिक और फली भी पौध में ऊपर की ओर पाई जाती है। पौधा कम फैलाव के साथ ही हार्वेस्टर से कटाई के दौरान दाने नीचे टूटकर कम गिरते हैं। चने की ये वैरायटी 110- 115 दिन में पक जाती है। इसके दाने आकार में बड़े, कत्थई रंग के होते हैं। तना मोटा और मजबूत होता है। पकने पर ये गिरेगा नहीं। ये चना पुख्ता उकता रोग, सूखने और सड़न से खुद को बचाता है। इसकी पैदवार एक हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल तक होगी।

जेजी-11, 14 और 24 चने की खासियत

» 110- 115 दिन में पक जाती है। इसकी फसल, दाना बड़ा, तना मोटा और मजबूत होते हैं।

» जवाहर चना-11 और जवाहर चना-14 किसानों के बीच पहली पसंद बना हुआ है।

» जेजी-11 दक्षिण भारत के लिए खासकर सूखा प्रतिरोधी उच्च

» उत्पादन वाली किस्म है। इसकी पैदावार 15 से 18 क्विंटल प्रति हंक्टेयर होगी।

» वर्तमान में जेएनकेविवि कि यह प्रजाति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के बीच बहुत अधिक पॉपुलर है।

» जेएनकेविवि ने अब तक चने की सात प्रजातियों को विकसित की है।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान , गुजरात , छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चने की बोवनी होती है। पूरे देश में चने के उत्पादन में एमपी पहले और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के स्थापना काल से अब तक चने की 7 प्रजातियों को किसानों के लिए तैयार किया गया है।
-डॉ. पीके बिसेन, कुलपति, डॉ. जीके कोतू, संचालक अनुसंधान, जेएनकेविवि, जबलपुर

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)